नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 250
दि. 10.01.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी ने यूपी दिवस 2026 की तैयारियों की प्रगति को लेकर उच्चाधिकारियों संग समीक्षा बैठक

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवसझ्र2026 की तैयारियों की प्रगति को लेकर उच्चाधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम बने। आगामी 24 से 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी जनपदों, देश के सभी राजभवनों एवं विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में यूपी दिवस का भव्य आयोजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी दिवसझ्र 2026 का मुख्य समारोह आयोजित होगा। प्रदेश की ऐतिहासिक और वैचारिक विरासत को जनमानस से जोड़ने के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभभाई पटेल, वंदे मातरम्–आनंद

मठ और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर से जुड़े नाट्य मंचनों का आयोजन किया जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा वंदे मातरम् रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आनंद मठ आधारित विशेष प्रस्तुतियां प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप देंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूपी दिवसझ्र2026 के अवसर पर देश–विदेश में बसे प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों से संवाद स्थापित किया जाए। इसके साथ ही राजभवनों व दूतावासों में मंत्रीगण की उपस्थिति में आयोजन किया जाए, वहीं जनपद स्तर पर उद्यमी, किसान, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, महिलाएं एवं उत्कृष्ट नागरिक 'यूपी गौरव' सहित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किए जाएं। यूपी दिवसझ्र2026 को जन उत्सव का स्वरूप देते हुए सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नाट्य मंचन, लोक–संगीत, ओडीओपी, ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक और आधुनिक तकनीक आधारित 3–डी, वीआर, 360ड टूर व लघु फिल्में, क्विज प्रतियोगिताएं और छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित होंगी। 'विकसित यूपीझ्र विकसित भारत' थीम पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी से आयोजन को नई ऊर्जा मिलेगी।

कड़ाके की ठंड में 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 29 शहरों में शीतलहर, आईएमडी की नई चेतावनी

(जीएनएस)।

देश के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं घना कोहरा सड़कों को निगल रहा है तो कहीं सर्द हवा हड्डियों तक चुभ रही है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी क्टऊ ने 10 जनवरी 2026 के लिए ऐसा अपडेट जारी किया है जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर और पूर्वी भारत के 29 शहर शीतलहर की गिरफ्त में हैं तो दक्षिण के चार राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है।

पहाड़ों से लेकर मैदान और समुद्र तक मौसम का मिजाज एक साथ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्टऊके मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले पांच से सात दिनों तक सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है।

मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी अगले दो से तीन दिनों तक यही हाल रहने वाला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनने वाली है यानी दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी।

कहां कहां चलेगी शीतलहर?

राजस्थान में 11 से 14 जनवरी 10 और 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी है। 10 जनवरी को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार भी इसी ठंडे झटके की चपेट में रहेंगे। तक शीतलहर का असर बना रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है।

चार राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे अवदाब ने दक्षिण भारत का मौसम उलट कर रख दिया है। क्टऊ ने अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के लिए 10 जनवरी को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी को भी कुछ इलाकों में तेज बरसात हो सकती है।

इस बारिश से इन राज्यों में तापमान तीन से चार डिग्री तक गिर सकता है जिससे ठंडक और बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों में समुद्र बहुत उग्र रहने वाला है इसलिए मछुआरों को तट से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है।

तमिलनाडु तट पर समुद्र का रौद्र रूप

तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। खाड़ी एरिया और गल्फ ऑफ मन्नार में समुद्र की हालत बहुत खराब रहने वाली है। ऐसे में किसी भी तरह की समुद्री गतिविधि खतरनाक साबित हो सकती है।

29 शहर में कोल्ड वेब का अलर्ट

पूर्वी भारत में बिहार के पूर्णिया,

हमारी नीति किसी के दवाब में नहीं बदलेगी', ट्रंप की धमकी पर भारत का करारा जवाब

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हालिया प्रेस वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय भू–राजनीति पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका द्वारा रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर प्रस्तावित 500% टैरिफ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके साथ ही, मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव पर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता

अमेरिका के प्रस्तावित 500% टैरिफ बिल पर भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी बाहरी दबाव में नहीं बदलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की जरूरतों के लिए 'सस्ती ऊर्जा' जुटाना प्राथमिकता है। भारत ग्लोबल मार्केट के बदलते स्वरूप के अनुसार अलग–अलग स्रोतों से तेल और यूरेनियम खरीदना जारी रखेगा। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक संप्रभु मुद्दा है, जिसे बाजार की गतिशीलता और घरेलू जरूरतों के आधार पर ही तय किया जाएगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता पर दिए गए बयानों का खंडन किया है। टएअ प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि दोनों देश पिछले साल फरवरी से एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए निरंतर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने लुटनिक की टिप्पणियों को 'गलत' बताते हुए कहा कि हम कई बार समझौते के बेहद करीब रहे हैं।

: घाटकोपर मेट्रो को 7 साल के इंतजार के बाद मिलेगी ये सुविधा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

मुंबई मेट्रो के सबसे व्यस्त घाटकोपर स्टेशन को आखिरकार 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय तक

यात्रियों की मांग और मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। घाटकोपर स्टेशन के मुंबई मेट्रो एंड पर प्रस्तावित चौड़ा एलिवेटेड डेक बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह डेक स्टेशन के उस हिस्से पर बनाया जा रहा है, जहां मेट्रो लाइन–1 (ब्लू लाइन) से उतरने वाले हजारों यात्री सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनों से जुड़ते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में नवगठित शामलाजी तहसील में विकास उत्सव मनाया गया

प्रसिद्ध यात्राधाम शामलाजी में शामलाजी महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति

शामलाजी मंदिर में दर्शन और पूजा–अर्चना की

अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी

गांधीनगर, 09 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शामलाजी में मनाए जा रहे शामलाजी महोत्सव का समापन करते हुए अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शामलाजी को नई तहसील घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम– शामलाजी महोत्सव पूरे अरवल्ली जिले के लिए विकास उत्सव बन गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अरवल्ली जिले के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत किए गए 1232 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और वंचितों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विकास कार्यों में कभी धन की कमी नहीं पड़ने दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की दिव्यता एवं भव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास करने का दृष्टिकोण साकार किया है।

उन्होंने साफ कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को आवास, अभ्यास (शिक्षा), आजीविका और आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर उप जिला अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन जनजातीय क्षेत्रों में 12 साइंस कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी और 11 मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से आदिवासी परिवारों की संतानों के लिए भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दिशा खुली है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदिवासियों की परंपरागत कला, कौशल, पेशों और उत्पादनों को वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के माध्यम से प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया।

मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व विकास किया है।

विशेषकर, अरवल्ली जिले के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा ने कहा कि शामलाजी महोत्सव आदिवासी समुदाय की एकता, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है और इस वर्ष हजारों लोगों की भागदारी और कलाकारों के लोकसंगीत, नृत्य एवं भक्तिमय वातावरण से समुदाय की विरासत और अधिक मजबूत बनी है। उन्होंने कहा कि आज मिले विकास कार्यों और लोकार्पण से अरवल्ली के विकास को और गति मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग (राज्य) की 107.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, शिक्षा विभाग की 24.49 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, खेल विभाग की 19.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) की 12.5 कोरड़ रुपए की परियोजनाओं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 3.46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

उन्होंने घुमंतू और विमुक्त जाति के परिवारों को भूखंड आवंटन के आदेश और किशन मिशन मंगलम समूह को कैश क्रेडिट सहायता वितरण किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका डामोर, सांसद श्रीमती शोभनाबेन बारैया, विधायक सर्वश्री भीखूसिंहजी परमार, धवलसिंह झाला, जिला प्रभारी सचिव श्री रूपवंत सिह, जिला कलेक्टर श्री प्रशस्ति पारिक, जिला विकास अधिकारी श्री दीपेश केडिया, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोहरसिंह जाडेजा सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस बार टीएमसी छोड़ बीजेपी का झंडा थाम सकती हैं फेमस एक्ट्रेस नुसरत जहां, मिल रहे नए संकेत!

अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद नुसरत जहां

फिर चर्चा में हैं। उनके पार्टनर और अभिनेता यश दासगुप्ता को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कयासों का दौर शुरू हो गया है।

'ईडी–दीदी टकराव' के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट में जबरदस्त हंगामा, सुनवाई 14 जनवरी तक टली

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे–वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी क्–ढअउ के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।

कोलकाता हाई कोर्ट में शुक्रवार, 9 जनवरी को उस वक्त अफरा–तफरी मच गई, जब तृणमूल कांग्रेस और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई शुरू होनी थी।

ईडी रेड से जुड़े इस केस में सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। बढ़ते हंगामे और अव्यवस्था के चलते हाई कोर्ट को मजबूरन सुनवाई टालनी पड़ी।

कोर्टरूम में उमड़ी भीड़, बिगड़े हालात

ममता बनर्जी सरकार और ईडी की कार्रवाई से जुड़े इस मामले को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गरम था। इसी वजह से जैसे ही केस को जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में पुकारा गया, बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग कोर्टरूम में जमा हो गए।

स्थिति यह हो गई कि कोर्टरूम पूरी तरह खचाखच भर गया और बैठने तक की जगह नहीं बची। जस्टिस शुभ्रा घोष ने कोर्ट से जुड़े लोगों के अलावा बाकी सभी से बाहर जाने का अनुरोध किया, ताकि सुनवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। हालांकि, इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई और अफरा–तफरी की स्थिति बनी रही।

बताया जा रहा है कि भीड़ और हंगामे के चलते कोर्ट की गरिमा और सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई। हालात जब काबू से बाहर होते नजर आए, तो जस्टिस शुभ्रा घोष ने बिना किसी सुनवाई के ही कोर्टरूम छोड़ दिया। इसके बाद आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी गई कि मामले की सुनवाई अब 14 जनवरी तक के लिए स्थगित की जाती है।

एऊरेड मामला पहले से ही सियासी

गौरतलब है कि यह पूरा मामला कोलकाता में क्–ढअउ ऑफिस पर हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता चुकी हैं। वहीं ईडी का दावा है कि वह कानून के दायरे में रहकर जांच कर रही है।

'मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव', ED रेड के बाद ममता का चौंकाने वाला दावा, कोलकाता से दिल्ली तक हड़कंप

(जीएनएस)।

कोलकाता की सड़कों पर गुस्सा, हाथों में पोस्टर और मंच से सीधे केंद्र सरकार को खुली चुनौती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के बाद जो कहा, उसने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। ममता ने ऐलान कर दिया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह कोयला घोटाले की पूरी परतें खोल देंगी।

8 जनवरी को ईडी ने ळटउ के आईटी सेल प्रमुख और क्–ढअउ से जुड़े प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। इसके बाद ळटउ ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध का बिगुल फूंक दिया। खुद ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर 9 जनवरी को उतरीं, मार्च निकाला और ईडी के खिलाफ दो एफआईआर भी दर्ज कराईं।

ममता सिर्फ विरोध तक नहीं रुकीं। वह रेड के दौरान जांच स्थल पर भी पहुंचीं और वहां से फाइलें और पेन ड्राइव लेकर बाहर आईं। उनका कहना था कि ईडी उनके पार्टी के

संवेदनशील चुनावी डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश कर रही थी।

भीड़ को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि उनके पास अमित शाह से जुड़े पेन ड्राइव हैं। उनका दावा था कि कोयला घोटाले का पैसा दिल्ली तक पहुंचता है और इसमें सीधे गृह मंत्री का नाम जुड़ा है। ममता ने कहा कि वह अपने पद की गरिमा की वजह से अब तक चुप थीं, लेकिन अगर उन्हें उकसाया गया तो वह सबकुछ जनता के सामने रख देंगी।

उनका आरोप था कि इस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल सुवेंदु अधिकारी ने किया और वही रकम अमित शाह तक पहुंचाई गई। ममता ने कहा कि पूरे देश को तब झटका लगेगा, जब ये सबूत सामने आएंगे।

ममता बनर्जी ने कहा,

"दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं ऐसे तो प्रतिक्रिया नहीं देतीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं।"

ममता ने कहा,

"मेरे पास पेन ड्राइव हैं। मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं, उसकी इज्जत करते हुए चुप रही हूं। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। मैं सब कुछ बता दूंगी। पूरा देश चौंक जाएगा।"

बीजेपी नेताओं पर सीधे हमले

ममता ने सिर्फ अमित शाह का ही नहीं, बल्कि बंगाल के कई बीजेपी नेताओं का भी नाम लिया। उन्होंने सांसद जगन्नाथ सरकार को "डकैत" कहा और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को "गद्दार" और अमित शाह का "नया दत्तक पुत्र" बताया। ममता का आरोप था कि कोयला घोटाले का पैसा इन्हीं रास्तों से घूमकर ऊपर तक गया।

उन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर ये एजेंसियां ईमानदारी से काम करतीं तो अवैध कोयला तस्करी रुक सकती थी।

ममता ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में बैठा एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोगी विभाग में काम कर चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति से निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह हरियाणा और बिहार में सत्ता हासिल की गई, वही मॉडल अब बंगाल में लागू किया जा रहा है।

उन्होंने रक्फ़ के नाम पर बंगाली बोलने वालों को परेशान करने का आरोप लगाया।

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना अंतर्गत एक दिवसीय जनपद स्तरीय किसान मेला एवं सह प्रदर्शनी का आयोजन

एसएसडी

बक्शी का तालाब, 8 जनवरी

बक्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय एक दिवसीय किसान मेला एवं सह-प्रदर्शनी, कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन कृषि विभाग जनपद लखनऊ के द्वारा किया गया। मेला एवं प्रदर्शनी की शुरूआत बक्शी का तालाब के क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला ने फीता काटकर की तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया एव सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मेला एवं प्रदर्शनी की शुरूआत की । उप कृषि निदेशक विनय कौशल ने आत्मा योजना की रूपरेखा एवं कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। तथा सभी किसानों, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों तथा छात्र -छात्राओं का स्वागत किया। कृषि विभाग के सलाहकार सुरेश कुमार राजपूत ने मेला एवं प्रदर्शनी की रुपरेखा बतायी तथा प्राकृतिक खेती पर विस्तृत चर्चा की। कृषि विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ ए के दुबे ने समसामयिक फसलों में कीट रोग प्रबंधन तथा अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों पर चर्चा किया। अपर जिला कृषि अधिकारी हर्षित त्रिपाठी ने मृदा के गिरते स्वास्थ्य पर चर्चा की और कहा की समय पर किसानों को मिट्टी की जांच कराना चाहिए तथा दलहनी खेती पर जोर दिया। । मुख्य अतिथि योगेश शुक्ला ने प्रदेश सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी तथा बताया कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है जिससे जनपद के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के कृषि कीट विज्ञान विभाग के सह -आचार्य डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने आलू और सरसों की खेती तथा उन पर लगने वाले रोग एवं कीटों पर पर चर्चा की। इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक दयाशंकर सिंह ने एफपीओ के बारे में विधिवत बताया तथा एफपीओ से ही किसानों की आय बढ़ सकती है।

दिल्ली वाले सावधान! राजधानी में 2 दिन पानी की किल्लत, कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित ?

(जीएनएस)।

दिल्लीवासियों को अगले दो दिनों तक पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (ऊखइ) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 9 जनवरी 2026 की शाम और 10 जनवरी 2026 की सुबह राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद या बेहद कम प्रेशर पर रहेगी।

जल बोर्ड के मुताबिक, यह असुविधा पाइपलाइन इंटरकनेक्शन वर्क और जलाशयों की सालाना फ्लशिंग प्रक्रिया की वजह से हो रही है। ऊखइ ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें। जानिए किन-किन इलाकों में पानी नहीं आएगा... इंद्रावल वाटर वर्क्स के अंतर्गत आने वाले जलाशयों में वार्षिक फ्लशिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया

होती है, जिसमें जलाशयों की सफाई की जाती है ताकि पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। इस फ्लशिंग प्रक्रिया के चलते हिंदू राव रिजर्वॉयर से पानी पाने वाले इलाकों में दो दिनों तक सप्लाई प्रभावित रहेगी।

इसके अलावा, पश्चिमी दिल्ली में 900 मिमी व्यास की नई पानी की पाइपलाइन को छह अलग-अलग स्थानों पर इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, जिससे वहां भी जल आपूर्ति रोकी जा रही है। नई 900 मिमी डायामीटर की ख्याला मेन पाइपलाइन को इन 6 जगहों पर जोड़ा जा रहा है। जिसमें पंजाबी बाग क्लब, पंजाबी बाग रिजर्वॉयर, राम देव मार्ग, ख्याला इढर और नजफगढ़ नाले के दोनों ओर जोड़ा जा रहा है। इसी तकनीकी काम की वजह से कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी।

इन इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत

नारायणा कमांड एरिया, इंदरपुरी, तोड़ापुर गांव, नारायणा गांव, नारायणा विहार, कृषि कुंज, मानसरोवर गार्डन, राजौरी गार्डन और आसपास, राजौरी गार्डन

इंदौर : पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत तीन की मौत, बायपास पर कार-ट्रक का एक्सीडेंट

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार अलसुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। तेजाजी नगर बायपास पर रालामंडल के समीप एक तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई।

इस हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं वर्तमान में राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है।

अलसुबह हुआ हादसा, कार के उड़े परखच्चे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा तड़के उस वक्त हुआ जब कार तेजाजी नगर बायपास से गुजर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

हादसे में प्रेरणा बच्चन, मन संधू और प्रखर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार घायल युवती की हालत नाजुक बनी हुई है।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

हादसे की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और संभवतः लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

'सीएए आंदोलन से दिल्ली दंगों से पहले अलग हो चुका था', शरजील इमाम का अदालत में दावा

(जीएनएस)।

स्टूडेट एक्टिविस्ट और 2020 दिल्ली दंगे के आरोपों में जेल में बंद शरजील इमाम ने अदालत में बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से काफी पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था।

इमाम ने कहा कि उनके कुछ सह-आरोपियों ने ही उनसे आंदोलन से दूर रहने को कहा था, क्योंकि उनके भाषणों से आंदोलन को "सांप्रदायिक रंग" मिलने की आशंका जताई जा रही थी। यह बयान इस मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब शरजील इमाम ने खुद को अन्य सह-आरोपियों से स्पष्ट रूप से अलग करने

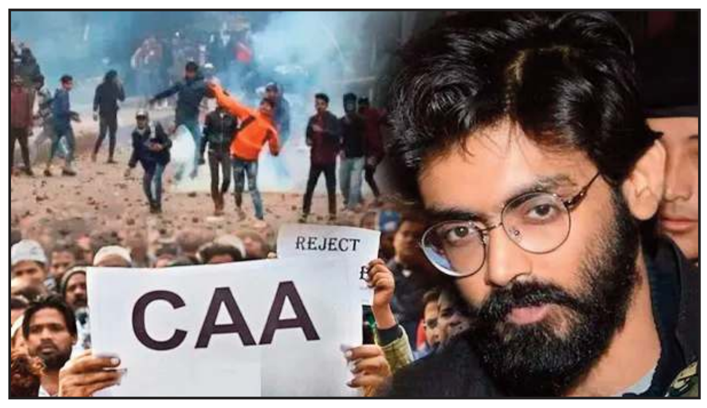

की कोशिश की है।

अदालत में क्या बोले शरजील इमाम के वकील?

कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज के समक्ष पेश होते हुए शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के ही रिकॉर्ड से यह साफ होता है कि इमाम को आंदोलन के बीच में ही किनारे कर दिया गया था और फरवरी 2020 के दंगों से जुड़ी किसी भी कथित साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

मुस्तफा ने अदालत में कहा,अन्य आरोपियों को लगने लगा था कि आंदोलन सांप्रदायिक दिशा में जा रहा है और चूंकि शरजील इमाम एक जाना-पहचाना चेहरा थे, इसलिए उन पर इसका आरोप आएगा। इसी वजह से उन्होंने 2 जनवरी 2020 तक आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। उस समय तक कहीं भी हिंसा नहीं हुई थी।"

दिसंबर 2019 तक सीमित भूमिका

पहले गोली मारेंगे, बाद में बात करेंगे', डेनमार्क ने ट्रंप को सिखाई तमीज, दिया तगड़ा डोज

(जीएनएस)।

डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को कथित तौर पर एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है, तो डेनिश सैनिकों को "पहले गोली चलाने और बाद में सवाल पूछने" की अनुमति होगी। यह निर्देश ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दे रहे हैं।

ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है

ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। अमेरिका की ओर से बार-बार दिए जा रहे बयानों के कारण डेनमार्क में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने पुराने लेकिन अब भी लागू नियमों की पुष्टि की है।

डेनिश अखबार 'बर्लिंग्सके' का बड़ा खुलासा

स्थानीय अखबार 'बर्लिंग्सके' से

बातचीत में डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर वहां किसी भी विदेशी ताकत द्वारा हमला किया जाता है, तो सैनिकों को किसी वरिष्ठ अधिकारी या सरकार के आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति होगी।

1952 के शीत युद्ध काल के नियम का हवाला

यह आदेश कोई नया नियम नहीं है। यह 1952 के शीत युद्ध (उङ्ग्र्रि हं१) के दौर में बनाए गए एक नियम का हिस्सा है। इस नियम के तहत सैनिकों को किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में "तुरंत मोर्चा संभालने" और जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

आदेश आए या न आए, कार्रवाई जरूरी

एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के अनुसार, इस नियम में साफ लिखा है कि सैनिकों को "आदेशों का इंतजार किए बिना या मांगे बिना" कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही उनके कमांडर को यह जानकारी न हो कि युद्ध की औपचारिक घोषणा हुई है या नहीं।

1940 के नाजी हमले से जुड़ी है इस नियम की जड़

इस नियम की जड़ें 1940 में हुए नाजी जर्मनी के हमले से जुड़ी हैं। उस समय जर्मन सेना ने कोपेनहेगन समेत डेनमार्क के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। डेनिश सेना उस हमले का प्रभावी तरीके से मुकाबला नहीं कर पाई थी।

उसी हार से जन्मा "पहले गोली" वाला सिद्धांत

1940 की उस हार के बाद डेनमार्क ने महसूस किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। इसी सोच से "पहले गोली चलाने" का नियम बनाया गया, ताकि सैनिक किसी भी हमलावर के सामने हिचकिचाएं नहीं। यह आदेश तब से आज तक लागू है।

डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं?

अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? हाल के वर्षों में ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है।

थलपति विजय की 'जन नायकन' पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBFC को दिया ऐसा आदेश

(जीएनएस)।

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की बहुचर्चित फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चल रहा सर्टिफिकेशन विवाद अब आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म की रिलीज को लेकर बीते दिनों काफी हंगामा देखने को मिला था लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद मेकर्स और फैंस दोनों को बड़ी राहत मिली है।

मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को दिया ऐसा आदेश

कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है कि फिल्म को व/अ सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिससे इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।

खंल्ल ठंटॅल्ल

9 जनवरी 2026 की रिलीज क्यों टली थी?

-दरअसल थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को पहले 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। इसी दिन प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी रिलीज हो रही थी।

-हालांकि आखिरी समय पर उइत्र्छ से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण थलपति विजय की फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा था जिससे फैंस में नाराजगी देखने को मिली थी।

हाई कोर्ट ने उइत्र्छ के फैसले को बताया गलत

-मामला जब मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उइत्र्छ की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा कि उइत्र्छ चेयरपर्सन के पास फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का अधिकार नहीं था।

-इसके साथ ही कोर्ट ने गत 6 जनवरी 2026 को जारी किए गए उइत्र्छ के लेटर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड को तुरंत व/अ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है।

अब कौन देख सकता है 'जन नायकन'?

व/अ सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के लिए नियम भी साफ हो गए हैं। अब इस फिल्म को सभी उम्र के दर्शक देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे केवल पैरेंट्स या गार्जियन के साथ थिएटर में एंट्री ले सकते हैं। वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए कोई रोक नहीं होगी।

27 कट लगाने के बाद भी अटका था मामला

-जानकारी के अनुसार 'जन नायकन' को 18 दिसंबर 2025 को CBFC के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। उस वक्त बोर्ड की ओर से फिल्म में 27 कट लगाने के निर्देश दिए गए थे।

वेनेजुएला मुद्दे पर ट्रंप को झटका,अमेरिकी सीनेट ने सैन्य कार्रवाई के अधिकार पर लगाई लगाम

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने एक अहम प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से राष्ट्रपति को रोकने के पक्ष में वोट किया है।

यह प्रस्ताव 52-47 मतों से पास हुआ, जिसमें ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी उनके खिलाफ मतदान कर दिया। इससे न केवल ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति भी खुलकर सामने आ गई है।

क्या है पूरा मामला?

सीनेट में लाया गया यह प्रस्ताव वेनेजुएला में संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया था। प्रस्ताव के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या सैन्य अभियान कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं चला सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में आगे कोई सैन्य कदम उठाना चाहता है, तो उसे पहले अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी।

यह फैसला राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के सैन्य कार्रवाई कितनी दूर तक कर सकता है।

ट्रंप की पार्टी में भी फूट

इस वोटिंग की सबसे अहम बात यह रही कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। जिससे वोटिंग में ट्रंप के पक्ष में 47 वोट और उनके खिलाफ 52 वोट पड़े। इससे यह साफ हो गया है कि वेनेजुएला नीति को लेकर खुद रिपब्लिकन खेमे में भी असहमति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप के तरीकों को लेकर बढ़ती बेचैनी का संकेत है।

अभी कानून बनना बाकी

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। अमेरिकी व्यवस्था के अनुसार, इसे संसद के दूसरे सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा। ट्रंप के पास इसे वीटो करने का अधिकार भी है, लेकिन सीनेट में हुई यह वोटिंग उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती है।

वोटिंग का क्या होगा असर?

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले के कई असर हो सकते हैं-

राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।

अमेरिकी सेना बिना संसद की मंजूरी के किसी भी कार्रवाई से पहले ज्यादा सतर्क रहेगी।

रूस और चीन को यह संदेश जाएगा कि अमेरिका की सत्ता व्यवस्था के भीतर मतभेद हैं।

ग्रीनलैंड जैसे मामलों पर यूरोप को कुछ राहत महसूस हो सकती है।

भारत जैसे देशों के "स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सकती है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी सख्ती जारी

सीनेट के इस फैसले के बावजूद अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी सख्ती कम नहीं की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी अमेरिकी सेना कैरिबियन क्षेत्र में तैनात है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ड्रग तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल जहाजों और नावों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला की ओर जा रहे एक रूसी तेल टैंकर को भी जब्त किया था, जिससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है।

ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम नेता और मादुरो की पूर्व सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने अमेरिका की शर्तें नहीं मानीं, तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोलंबिया और ग्रीनलैंड के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।

ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है और वहां के विशाल तेल उद्योग को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहता है। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस रणनीति में अमेरिकी सेना की भूमिका क्या होगी और भविष्य में इसे किस तरह लागू किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट का यह फैसला ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

क्या है DIRBS तकनीक? जिसने एक झटके में 10 करोड़ मोबाइल फोन्स को बना दिया डब्बा

(जीएनएस)।

पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) ने वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि देश में सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के चलते लगभग 10 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई का मुख्य निशाना नकली, क्लोन किए गए और चोरी के फोन रहे हैं।

इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के घरेलू मोबाइल निर्माण उद्योग को भी जबरदस्त संजीवनी मिली है। भारत जैसे बड़े मोबाइल बाजार के लिए यह एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक के जरिए सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को सुधारा जा सकता है।

नकली और क्लोन डिवाइस पर कड़ा प्रहार

PTA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक किए गए कुल 10 करोड़ हैंडसेट्स में से लगभग 7.2 करोड़ फोन नकली या डुप्लीकेट पाए गए। इसके अलावा, 2.7 करोड़ ऐसे फोन थे जिनके क्टएक नंबरों के साथ छेड़छाड़ या क्लोनिंग की गई थी। इस बड़े पैमाने पर की

गई कार्रवाई ने उन अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ दिया है जो सस्ते और असुरक्षित डिवाइस बेचकर ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनिवार्य था।

DIRBS: सुरक्षा और नेटवर्क का तालमेल

DIRBS एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट रेगुलेशन के तहत लागू किया गया है। यह सिस्टम हर मोबाइल के रजिस्ट्रेशन को उसके नेटवर्क ऑथराइजेशन से जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग या अनधिकृत तरीके से लाए गए फोन अब काम नहीं कर पाएंगे। केवल वही डिवाइस सक्रिय हो सकेंगे जो नियमों के अनुरूप हैं। इस पारदर्शिता ने अवैध तस्करी पर लगाम लगाई है और मोबाइल मार्केट को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है।

स्थानीय निर्माण में ऐतिहासिक उछाल

सख्त नियमों का सबसे सकारात्मक असर पाकिस्तान के घरेलू उद्योग पर दिखा है। साल 2025 तक पाकिस्तान में उपयोग होने वाले 95% डिवाइस स्थानीय स्तर पर ही निर्मित हो रहे हैं, जिनमें 68% स्मार्टफोन्स शामिल हैं। सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसी 36 प्रमुख कंपनियों ने वहां अपनी यूनिट्स स्थापित की हैं। जब नकली और स्मगल किए गए विदेशी फोन ब्लॉक हुए, तो बाजार में मांग बढ़ी, जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार के नए अवसरों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है।

भारत के लिए सबक

भारत में भी नकली और क्लोन स्मार्टफोन्स का बाजार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी उ्क्रम्इर जैसा सख्त सिस्टम अपनाना चाहिए। इससे न केवल कर चोरी रुकेगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि उन करोड़ों ग्राहकों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी जो अनजाने में असुरक्षित और नकली प्रीमियम डिवाइस खरीद लेते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

सीआईए ने पहले कर रख रखी थी मादुरो को अचानक सत्ता से हटाये जाने के बाद के हालात का आंकलन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान को अधिकृत करने से ठीक पहले अमेरिका की गुप्तचर सेवा सीआईए ने एक गोपनीय आंकलन पूरा किया जिसमें यह जांच की गई कि अगर मादुरो को अचानक सत्ता से हटा दिया जाता है तो वेनेजुएला की आंतरिक स्थिति वैसी होगी? न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप द्वारा प्रात्यक्ष कार्रवाई के जोखिमों और परिणामों का आवलन करने के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने गुप्त विश्लेषण का अनुरोध किया था। रिपोर्ट में अमेरिका के नेतृत्व में तख्तापलट की संभावना पर कम और मादुरो के लिए व्यावहारिक निकास परिदृश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें बातचीत के माध्यम से समझौते, निरन्तर अमेरिकी दबाव और अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग शामिल थे।

खुफिया आंकलन से अवगत लोगों ने बताया कि सीआईए ने मादुरो के पद छोड़ने के लिए एक ही संभावित परिणाम की कल्पना करने के बजाए कई विकल्पों पर विचार किया। इनमें बातचीत के जरिए सत्ता हस्तांतरण शामिल था, जिसमें मादुरो स्वेच्छा से पद छोड़ देते, प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के माध्यम से दबाव बढ़ाना और अन्य विकल्पों के विफल होने पर जबरन निष्कासन की संभावना शामिल थी। इस विश्लेषण का उद्देश्य ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के एक अत्याधिक सुरक्षित सैन्य ठिकाने के खिलाफ उच्च जोखिम वाले अभियान की मंजूरी देने पर विचार करते समय उच्चस्तरीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना था। रिपोर्ट से परिचित अधिकारियों ने कहा कि इसमें राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीआईए की नजर में सबसे संभावित उत्तराधिकारी कौन था? इस आकलन के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक उत्तराधिकारी पर इनका दृष्टिकोण था, उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज। रोड्रिगज को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जो मादुरो को हटाए जाने की स्थिति में तुरन्त सत्ता संभालने के लिए सबसे उपयुक्त थीं। हालांकि कुछ सांसदों और वेनेजुएला के नागरिकों ने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को संभावित वैकल्पिक नेता के रूप में देखा है, लेकिन खुफिया समीक्षाओं ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या उनके पास मादुरो के बाद की स्थिति में जल्दी से सत्ता संभालने के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचा या राजनीतिक प्रायास है? खुफिया जानकारी से परिचित अधिकारियों के अनुसार सीआईए को संदेह था कि क्या विपक्ष जनसमर्थन को राज्य संस्थाओं, सेना और सुरक्षा सेवाओं पर प्रभावी नियंत्रण में बदल पाएगा? चिता वैचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक थी, स्पष्ट और व्यवहार्य उत्तराधिकारी के बिना मादुरो को हटाने से अस्थिरता कम होने के बजाए और बढ़ सकती थी। सीआईए का यह आंकलन सही साबित होता दिख रहा है। वेनेजुएला में न तो सत्ता परिवर्तन हुआ और न ही मौजूदा सरकार और देशवासियों में अमेरिका के प्रति समर्थन बढ़ता दिख रहा है।

निकोलस मादुरो को तो हटा दिया पर फिलहाल उनके उत्तराधिकारी डेल्सी रोड्रिगज वैसी ही बातें कर रही हैं जैसे मादुरो करते थे। आगे चलकर बदल जाए तो और बात है। अभी तो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, डेल्सी रोड्रिगज ने कहा है कि देश पर वेनेजुएला की सरकार शासन कर रही है, न कि कोई विदेशी शक्ति। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। रोड्रिगज ने कहा यहां कोई युद्ध नहीं है क्योंकि हम युद्ध में नहीं हैं। हम एक शांतिप्रिय लोग हैं। एक शक्तिशाली देश हैं, जिस पर हमला किया गया और आक्रमण किया गया। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारी 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित तेल अमेरिका को हस्तांतरित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण में माइनिंग सेक्टर का रोडमैप तैयार करने का सक्षम मंच बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स लाए हैं
- गुजरात लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम क्षेत्र
- गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से 'विकसित भारत@2047' का संकल्प साकार करने में योगदान देने को प्रतिबद्ध

भारत का खनन क्षेत्र 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी

खनिज संपदा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

बिहार के उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के खान मंत्री हुए सहभागी

गांधीनगर, 09 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा गुरुवार को महात्मा मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर में कहा कि यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण का रोडमैप तैयार करने का एक सक्षम मंच बनेगा।

केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में प्रथम तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें देश के विभिन्न राज्यों के खान मंत्री और पदाधिकारियों सहित हितधारक भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों सर्वश्री जी. किशन रेड्डी, सी.आर. पाटिल, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय खान राज्य मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खान-खनिज देश के उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह चिंतन शिविर सामूहिक चिंतन-मंथन के माध्यम से इस आधार स्तंभ को और मजबूत बनाकर देश के विकास को एक नई गति देने का प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स (सुधार) लाए हैं। खनन क्षेत्र भी ऐसे रिफॉर्म्स का साक्षी रहा है। स्पष्ट नीतियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शी शासन के परिणामस्वरूप ये रिफॉर्म्स संभव हो पाए हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करने की जो परंपरा स्थापित की है, और ग्रीन माइनिंग, साइंटिफिक रेक्लेमेशन और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी से खनन क्षेत्र का विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात को लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम स्थान बताते हुए कहा कि खान-खनिज क्षेत्र को केवल उत्पादकता और नीलामी तक सीमित न रखते हुए गुजरात ने इसे पारदर्शिता, अनुशासन और नियम-कानूनों के अमल का प्रतीक भी बनाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खान से लेकर अंतिम गंतव्य स्थल तक के खनिज परिवहन की रीयल टाइम निगरानी के लिए जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' से 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने को प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री

जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मजबूत आधार स्तंभ करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात आज पूरे देश के लिए विकास का केंद्र बन गया है। गुजरात के मॉडल का अनुसरण करके आज देश के अनेक राज्यों के बीच विकास और निवेश के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में खनन क्षेत्र में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2014 की तुलना में मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज अन्वेषण में 190 फीसदी की वृद्धि हुई है। आयरन, लाइमस्टोन, लेड और जिंक जैसे खनिजों के उत्पादन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। पारदर्शी नीलामी प्रणाली और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमडब्ल्यू) के माध्यम से राज्यों के खनन राजस्व में बड़ा उछाल आया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल खनिजों के निष्कर्षण (पृथ्वी से खनिज निकालने की प्रक्रिया) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग, रीसाइक्लिंग और रीप्रोसेसिंग की पूरी 'वैल्यू चेन' पर ध्यान दे रहा है। वर्ष 2030 तक ई-वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना है। इसमें खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर ऑपरेशन तक के समय को न्यूनतम करना, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत को ग्लोबल प्रोसेसिंग हब बनाना जैसे विषयों पर अधिकतम फोकस करना शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनर्उपयोग के लिए 'अर्बन माइनिंग' और 'वेस्ट टू वेल्थ' के विचार को गति देने का आह्वान किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में खनिज क्षेत्र और जल प्रबंधन का परस्पर समन्वय बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जब 'विकसित भारत' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में खनिज संपदा को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहना गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति में इस मंत्रालय की भूमिका निर्णायक है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि खनिज उत्खनन के दौरान पर्यावरण और जल संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने 'माइनिंग विद माइंडफुलनेस' का मंत्र देते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के साथ खनन कार्य करने से ही दीर्घकालिक लाभ होगा। खनन प्रक्रिया में पानी का रीसाइकल और रीयूज अनिवार्य है। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करने की बात कही जिससे भूमिगत जलस्तर को नुकसान न पहुंचे।

श्री पाटिल ने कहा कि भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हम आयात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाएगी और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगी। शिविर के दौरान उन्होंने खान विभाग द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाली डिजिटल और नवीन पद्धतियों की प्रशंसा की।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने चिंतन शिविर को भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य के लिए एक निर्णायक मार्ग बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संग्रह के लिए आवश्यक बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 'क्रिटिकल मिनरल्स' के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ऐसी खानों की नीलामी और उत्पादन प्रक्रिया को तेज बना रही है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक उपकरणों का खनन क्षेत्र में उपयोग अनिवार्य है, जिससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि प्रदूषण, लागत और समय में भी उल्लेखनीय बचत होगी।

खनिज विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए श्री दुबे ने कहा कि खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ किया कि इस क्षेत्र में केवल सरकार की भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय खनन सचिव श्री पीयूष गोयल ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री कोल्लू रवीन्द्र, ओडिशा के मंत्री श्री विभूति भूषण जेना, तेलंगाना के मंत्री श्री विवेक वेंकट स्वामी, उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. अरुण कुमार, नागालैंड के मंत्री श्री चीनवेंग, गुजरात की उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा सहित केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

एप्लीकेशन के 3 दिन बाद जॉइनिंग,करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव, लालू परिवार का 7 डील वाला खेल

बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला 'नौकरी के बदले जमीन' मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य 41 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में इस पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित 'सिंडिकेट' की तरह संचालित बताया है।

सीबीआई (उइक) की जांच में दावा किया गया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के विभिन्न जोन में बिना किसी विज्ञापन या

पारदर्शी प्रक्रिया के लोगों को ग्रुप-डी की नौकरियां दी गईं। इसके बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से कौड़ियों के भाव बेशकीमती जमीनें लिखवाई गईं। यह मामला न केवल एक परिवार की कानूनी लड़ाई है, बल्कि भारतीय राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग की गहरी पड़ताल भी है।

'निजी जागीर' की तरह इस्तेमाल हुआ मंत्रालय

9 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय को उस दौरान एक 'निजी जागीर' की तरह चलाया गया। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 41 लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ढउ ङ्र3) और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, सबूतों के अभाव में 52 अन्य लोगों को राहत भी दी गई है।

ये भी पढ़ें: छंल्ल'ङ्क१ खड्ड उंरी: लालू परिवार पर शिकंजा, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 41 पर आरोप तय, अब जाना होगा जेल!

कैसे शुरू हुई जांच? 3.75 लाख की जमीन और 3 नौकरियां

इस घोटाले की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब पटना के किशुन देव राय का मामला सामने आया। 6 फरवरी 2008 को किशुन देव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन बाजार भाव से कहीं कम, महज 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम कर दी। सौदे के तुरंत बाद किशुन देव के परिवार के तीन सदस्यों को मुंबई स्थित मध्य रेलवे में नौकरी मिल गई। यहीं से जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के ठोस संकेत मिले।

4.39 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख में

उइकके अनुसार, 2004 से 2009 के बीच लालू परिवार ने भ्रष्टाचार के जरिए बिहार में एक लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन हासिल की।

कीमत का अंतर: जिस जमीन की बाजार कीमत उस समय लगभग 4.39 करोड़ रुपए थी, उसे सिर्फ 26 लाख रुपए में हथिया लिया गया।

बिना विज्ञापन भर्ती: मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे रेलवे जोन में नियुक्तियों के लिए कोई आधिकारिक विज्ञापन नहीं निकाला गया।

तीन दिन में जॉइनिंग: कुछ मामलों में तो आवेदन देने के मात्र 3 दिन के भीतर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।

सात जमीन सौदों में छिपा 'भ्रष्टाचार का मॉडल'

जांच एजेंसी ने कोर्ट के सामने सात ऐसे प्रमुख सौदों का जिक्र किया है, जो इस घोटाले की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं:

किशुन देव राय: जमीन के बदले परिवार के 3 सदस्यों को नौकरी मिली।

संजय राय: 3.75 लाख में जमीन दी, बदले में परिवार के 2 लोगों को रेलवे में काम मिला।

किरण देवी: मीसा भारती को जमीन बेची, अगले साल बेटे का चयन रेलवे में हो गया।

निजी कंपनी का खेल: हजारी राय की जमीन पहले 'एके इन्फोसिस्टम्स' जैसी कंपनी को दी गई, जिसका नियंत्रण बाद में लालू परिवार के पास आ गया।

लाल बाबू राय: बेटे को 2006 में नौकरी मिली और 2015 में जमीन राबड़ी देवी के नाम की गई।

गिफ्ट डीड: एक कर्मचारी ने नौकरी मिलने के बाद 62 लाख की जमीन लालू परिवार को 'गिफ्ट' कर दी।

हेमा यादव: रेलवे में नौकरी मिलने के कुछ समय बाद जमीन लालू की बेटी हेमा यादव के नाम ट्रांसफर की गई।

एउकी कार्रवाई और 600 करोड़ की संपत्ति

इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (एउ) ने अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित या जब्त किया है। इसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित पॉश बंगला भी शामिल है। उइकका दावा है कि कई जमीनों को महज 5,700 रुपए जैसी मामूली रकम पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम किया गया था, जबकि उस समय वे नाबालिग थे। आरोप तय होने के बाद अब 29 जनवरी 2026 से इस मामले का औपचारिक ट्रायल शुरू होगा।

कौन ये वाला सलमान खान, जो में भीड़ को उकसाने में बुरा फंसा? खुद बताई पूरी सच्चाई?

(जीएनएस)। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 6-7 जनवरी 2026 की रात एमसीडी की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा ने शहर को हिला दिया। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे हटाने पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला हुआ और कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, और CCTV फुटेज से 30 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की है।

इस हिंसा में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (क्ल्ला'ह्वील्ली१) का नाम भी जुड़ रहा है, जिनमें से एक है हाजी सलमान खान। आरोप है कि सलमान ने वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को भड़काया और मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए उकसाया। लेकिन सलमान ने खुद का निर्दोष बताते हुए कहा है कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। आइए, इस सलमान की बैकग्राउंड, आरोपों की सच्चाई और पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यह कहानी सोशल मीडिया की ताकत और गलत इस्तेमाल की है, जो हिंसा को भड़का सकती है...

तुर्कमान गेट इलाका दिल्ली का पुराना और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। 6 जनवरी की रात एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की। यहां बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानें थीं, जो कथित तौर पर मस्जिद की जमीन पर बनी थीं। कार्रवाई के दौरान लोकल लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर हमला हुआ, जिससे कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

इस हिंसा को 'सुनियोजित' बताया जा रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि सोशल मीडिया पर अफवाहें

फैलाई गईं - जैसे ' मस्जिद गिराई जा रही है' । व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज फॉरवर्ड हुए, जिससे भीड़ इकट्ठी हुई। अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और 10 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार है, जिनके पोस्ट्स स्कैन हो रहे हैं। सलमान खान इन्हीं में से एक हैं।

हाजी सलमान खान (उम्र: करीब 30-35 साल) गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और खुद को 'डिजिटल क्रिएटर' बताते हैं। सलमान की पहचान मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है - वे अल्पसंख्यक अधिकारों, सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक कैंपेन पर पोस्ट करते हैं। सलमान खुद को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रभार में ळटउ (तृणमूल कांग्रेस) के प्रदेश मंत्री बताते हैं, और ढटखए (प्रधानमंत्री जन विकास योजना) के प्रचार-प्रसार अभियान से जुड़े हैं। शिक्षा और बैकग्राउंडः सलमान ने मेरठ के शुभार्थी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की रवाडी (पालखी यात्रा) में ढोल-ताशों ने जमाया भारी आकर्षण

ढोल-ताशों के 50 कलाकारों द्वारा उमंगोल्लासपूर्ण वादन के साथ यात्री भी नाच उठे, तीन ढोल टूटे

गांधीनगर, 09 जनवरी : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत शुक्रवार को भव्य रवाडी (पालखी यात्रा) के दौरान समग्र सोमनाथ नगरी भक्ति एवं उत्साह से गूंज उठी। रवाडी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्त तथा श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागी हुए।

इस रवाडी के दौरान ढोल-ताशा कलाकारों ने अपनी मनमोहक तथा उमंगोल्लासपूर्ण प्रस्तुति से विशेष आकर्षण उत्पन्न किया। लगभग 50 कुशल कलाकारों ने ढोल और ताशों के ताल-लय के साथ परंपरागत संगीत

की प्रस्तुति कर वातावरण को रंगीन बना दिया। गगनभेदी नाद के साथ यात्री भी नाच उठे। वादन इतना उत्साहपूर्ण था कि लगभग तीन ढोल टूट गए। ढोल-ताशों के गूंजते नाद के साथ रवाडी आगे बढ़ रही थी, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर खड़े दर्शकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था।

कलाकारों की एकीकृत प्रस्तुति ने समग्र कार्यक्रम को लोकोत्सव के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया।

रवाडी के दौरान भक्तों द्वारा जय शिवशंकर तथा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सनातन संस्कृति की महिमा गुंजाई गई। ढोल-ताशों के ताल के साथ भक्ति तथा आनंद का अनूठे संगम का सृजन हुआ।

इस प्रकार; सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत निकली रवाडी में ढोल-ताशा कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम की भव्यता तथा सांस्कृतिक वैभव को और उजागर कर सभी उपस्थितों के लिए इस क्षण को यादगार बना दिया।

हनी सिंह पर टिकी स्मृति मंधाना की नजर, ओपनिंग सेरेमनी हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो हो रहा वायरल

(जीएनएस)। शुक्रवार की शाम को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में विमेंस प्रीमियर लीग (हढछ) चौथे सीजन का आगाज हुआ। टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के एक दमदार भाषण से हुई। उन्होंने समाज में महिला शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

हनी सिंह की दमदार एंट्री (हढछ 2026, ल्ह्वल्ली८ ऱ्ल्ल') हरनाज कौर संधू के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज ने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिल्म 'किक' के मशहूर गाने 'यार ना मिले' पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाए। शाम का सबसे बड़ा आकर्षण रहे रैपर यो यो हनी सिंह। सिर से पैर तक काले पहनावे में सजे हनी सिंह ने जैसे ही अपने सुपरहिट गाने 'मिलियनेयर' के साथ मंच पर एंट्री की, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा।

हनी पर टिकी मंधाना की नजर

हनी सिंह के साथ आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी नजर आईं। हनी सिंह के गानों और उनके डांस स्टेप्स ने सीजन की शुरुआत में जोश भर दिया। इस दौरान मंधाना की नजरें हनी पर टिक गई जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस धमाकेदार आगाज के बाद सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (फढ) की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (टक) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

आरसीबी ने जीता टॉस

मंधाना ने बताया कि रात में ओस की भूमिका को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ और नडीन डी क्लर्क के रूप में आरसीबी ने अपने चार विदेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया। वहीं मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि स्टार खिलाड़ी हेली मैथ्यूज तबीयत खराब होने के कारण इस ओपनिंग मैच का हिस्सा नहीं बन सकीं।

भूमि विवाद में मारपीट और जान से मारने की धमकी:रहीमाबाद में दो भाइयों सहित चार पर मुकदमा दर्ज, एक हिरासत में

मलिहाबाद (जीएनएस)।

लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के मुड़ियारा मजरा देवीखेड़ा निवासी अरविंद कुमार ने अपने भाई महेश और रूपचंद सहित दो अज्ञात लोगों पर भूमि विवाद को लेकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पीड़ित अरविंद के अनुसार, उनकी पुश्तैनी भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्षी पक्ष इस जमीन पर लगातार दबाव बना रहा है।

शिकायत के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 8 बजे अरविंद के भाई विपिन ने उन्हें फोन कर बताया कि अगले दिन विवादित भूमि पर विपक्षियों से बात होनी है। यह सूचना मिलने के बाद अरविंद अपने घर लौट रहे थे।

घर लौटते समय गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर ककरहिया खेड़ा गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे महेश, रूपचंद और उनके दो अज्ञात साथियों ने अरविंद को रोक लिया। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से अरविंद की पिटाई की।

अरविंद के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग मौके की ओर आने लगे। ग्रामीणों को आता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अरविंद को मलिहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

गौसेवा में समर्पित योगी सरकार, प्रदेश के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सुदृढ़ निगरानी

65 जिलों के गौ-आश्रय स्थलों पर मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू, शेष में प्रक्रिया जारी

20 जिलों के विकास भवनों में स्थापित केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं पर रखी जा रही सतत नजर

ठंड, भोजन, उपचार और आश्रय की समुचित व्यवस्था, गोवंश संरक्षण को मिली रफ्तार

लखनऊ, 9 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गौ-आश्रय स्थलों पर लगातार निगरानी, प्रबंधन और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों के कुल 6718 ग्रामीण गौ-आश्रय स्थलों में से 65 जनपदों के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। बाकी जनपदों में भी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। साथ ही प्रदेश के हरदोई, आगरा, जालौन सहित 20 जनपदों के विकास भवनों में केंद्रीकृत निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखी जा रही है।

गो-आश्रय स्थलों को यूपी सरकार दे रही है मूलभूत सुविधाएं

योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गौ-आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए शेड, स्वच्छ भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था, खड़ंजा, भूसा भंडार गृह, उपचार कक्ष, प्रकाश और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा रहा है।

20 जनपदों में स्थापित निगरानी कंट्रोल रूम

पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि गौ-आश्रय स्थलों की बेहतर निगरानी एवं व्यवस्था के समन्वय के लिए राज्य के 20 जनपदों के विकास भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हरदोई, आगरा, जालौन, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, पीलीभीत, कौशांबी, शामली, बस्ती, अंबेडकरनगर, बलिया, एटा, अमरोहा, फरुर्खाबाद और चंदौली में ये कंट्रोल रूम कार्यरत हैं। शेष जनपदों में भी चरणबद्ध ढंग से यह व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र मजबूत होने से गौवंश की देखभाल अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदाराना ढंग से हो रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो रही है।

ठंड से किसी गोवंश की मृत्यु न हो

गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के साथ-साथ ठंड से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थलों पर हरा चारा, तिरपाल, काउ-कोट, अलाव, औषधियां, उपचार सुविधा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठंड अथवा अव्यवस्था के कारण किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो।

बंथरा क्षेत्रान्तर्गत एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना

लखनऊ, थाना बंथरा, विषय झ थाना बंथरा क्षेत्रान्तर्गत एक अज्ञात महिला का शव आज दिनांक 09.01.2026 को प्रातः लगभग 09.00 बजे थाना बंथरा क्षेत्रान्तर्गत नारायणपुर बेहटा मार्ग ग्राम अमावा के सामने रोड के किनारे एक अज्ञात महिला (उम्र लगभग 50 वर्ष) का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना बंथरा पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

मौके पर की गई प्रारंभिक जांच से ज्ञात हुआ कि संभवतः उक्त महिला भिक्षावृत्ति कर जीवन-यापन करती थी तथा इसके बैग से शराब के पाउच एवं बीडी, कपड़े आदि भी बरामद हुए हैं। वर्तमान में महिला के नाम-पते के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है।

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर निरीक्षण कराया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया महिला की मृत्यु किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से होना प्रतीत हो रहा है।

महिला के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, जिससे मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आसपास के क्षेत्रों में जानकारी साझा की जा रही है।

प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

लोधेश्वर महादेव धाम में मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज:एकल अभियान ने शिक्षा, संस्कार के लिए किया आयोजन

रामनगर (जीएनएस)।

बाराबंकी की तहसील रामनगर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव धाम के प्रांगण में शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर एकल अभियान गतिविधि विभाग द्वारा खिचड़ी भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद की शाखा एकल अभियान के अंतर्गत बाराबंकी रामनगर महादेवा संयुक्त संच के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

खिचड़ी भोज कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. संदीप सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एकल अभियान समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कार और सेवा पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद बाराबंकी में वर्तमान में 330 ग्राम सभाओं में एकल अभियान के अंतर्गत कार्य संचालित हैं, जो सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर अनूप सिंह, रंजीत यादव, संच प्रशिक्षक रोशनी, संदीप शुक्ल और आंचल गतिविधि प्रमुख देवनारायण सिंह ने उपस्थित संच कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को एकल अभियान के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और समाज में इसके योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कार आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में एकल अभियान से जुड़ी अनेक महिलाएं एवं युवतियां भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने आयोजन में सक्रिय सहभागिता निभाई। इस दौरान संच प्रमुख रोशनी सिंह, आंचल प्रशिक्षक प्रमुख शांति प्रिया सिंह, रामनगर संच प्रियंका वर्मा, दुर्गेश्वरी आचार्या, रोली आचार्या सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया और सामाजिक समरसता तथा सेवा भावना का संदेश दिया।

आगरा पुलिस के उस समय हुई परेशान जब मुंबई के कारोबारी के अपहरण की सूचना मिली

आगरा, आगरा पुलिस के उस समय पसीने छूट गए जब मुंबई के कारोबारी के अपहरण की सूचना मिलीपुलिस ने इस मामले में तत्काल जांच तेज कर दी

पुलिस जांच में हकीकत कुछ ऐसी सामने आई, जिसे जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए

आगरा के एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे से मुंबई के कारोबारी के अपहरण की कहानी झूठी निकली

पुलिस के मुताबिक वह समलैंगिक फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए खुद उसकी कार में बैठे थे

कार में वीडियो बनाने पर विवाद हुआ। तब फ्रेंड ने मोबाइल और रुपये छीन लिए

साथियों को बुलाकर खेत में ले गए और खाते में 1.20 लाख रुपये ट्रांसफर कराने के बाद छोड़ा

व्यापारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी फ्रेंड सहित पांच को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है

लखनऊ में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र शुरू

योगी आदित्यनाथ सरकार की औद्योगिक नीति को मिला उद्योग जगत का भरोसा

योगी सरकार के सहयोग से रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र को तैयार किया जाना संभव हुआ : धीरज हिंदुजा

उत्तर प्रदेश बना हरित परिवहन और निवेश का नया केंद्र

लखनऊ, 09 जनवरीः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को वाहन निमार्ता कंपनी अशोक लेलैंड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन के साथ ही वाहन निर्माण और औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह संयंत्र विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे लखनऊ को हरित औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि योगी सरकार के सहयोग और प्रशासनिक तत्परता के कारण रिकॉर्ड समय में इस संयंत्र को तैयार किया जाना संभव हो सका।

योगी सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से निवेश को प्रोत्साहन

उद्घाटन के अवसर पर अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह कंपनी का पहला विनिर्माण संयंत्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए प्रदेश में एक सुदृढ़ और भरोसेमंद तंत्र तैयार किया गया है। आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी, प्रभावी कानून व्यवस्था और जवाबदेह प्रशासन आज उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रदेश में निवेश के साथ ही इससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। उन्होंने इस परियोजना को धरातल पर उतारने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व के साथ कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश 'फियरलेस बिजनेस', 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ट्रर्स्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि अशोक लेलैंड की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और आज कंपनी 15 देशों में भारतीय विनिर्माण क्षमता और तकनीकी सामर्थ्य का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही है।

निवेश के लिए स्थायित्व और भरोसे का माहौल

धीरज हिंदुजा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रक्षा तंत्र की मजबूती और स्थायित्व से देश में निवेश का भरोसेमंद वातावरण बना है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व में उद्योगों के लिए विकसित सकारात्मक माहौल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस और प्रभावी पहल की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में देश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया संयंत्र

अशोक लेलैंड कंपनी के अनुसार लखनऊ का यह संयंत्र भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आधुनिक विनिर्माण तकनीक और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से यहां तीव्र गति से इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जा सकेगा।

स्थानीय समुदाय के लिए लाभ और सामाजिक पहल

अशोक लेलैंड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि जहां भी अशोक लेलैंड का संयंत्र स्थापित होता है, वहां स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कंपनी की रोड टू स्कूल पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 25 हजार से अधिक छात्रों को पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

निवेश का नया अध्याय लिख रहा उत्तर प्रदेश, और तेज हुई औद्योगिक रफ्तार

योगी सरकार के संकल्प का लाभ उठाकर अशोक लीलैंड ने दो वर्षों से भी कम समय में निवेश को धरातल पर उतारा

प्रदेश सरकार के प्रयासों से यूपी में निवेश केवल एमओयू तक सीमित नहीं, बल्कि प्लांट और प्रोडक्शन में बदल रहा

उत्तर प्रदेश अब बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है

लखनऊ, 9 जनवरी। उत्तर प्रदेश अब निवेश और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यापक नीतिगत और विनियामक सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। इसी का ताजा उदाहरण है अशोक लीलैंड का नया प्लांट। यह प्लांट न केवल औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश अब बड़े निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

अशोक लीलैंड के इस प्लांट में लगभग 252 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस परियोजना के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 20 फरवरी 2024 को हुई थी। इतने कम समय में परियोजना का धरातल पर आ जाना इस बात का प्रमाण है कि अब निवेश केवल एमओयू तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि तेजी से प्लांट, उत्पादन और रोजगार में बदल रहा है। इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नया बढ़ावा मिलेगा।

राज्य में निवेश की यह सफलता किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं है। वर्ष 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसके बाद वर्ष 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश आशय पत्र प्राप्त हुए। कुल मिलाकर पौने 9 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसे चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों के माध्यम से धरातल पर उतारने की ठोस शुरूआत हुई है।

अब तक 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की 16,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं। इनमें से लगभग 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 8,300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं करीब 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 8,100 से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। यही नहीं, योगी सरकार जीबीसी 5 के माध्यम से फिर 6 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को जल्द ही जमीन पर उतारने जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि निवेश केवल कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में उद्योग और रोजगार में बदल रहा है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी इस प्रगति को स्पष्ट रूप से दशार्ता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मार्च 2025 में विनिर्माण का सूचकांक 167.97 और सामान्य सूचकांक 157.73 दर्ज किया गया।

यह बताता है कि प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अशोक लीलैंड का प्लांट इस पूरी यात्रा का मजबूत प्रतीक है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए केवल नीतियां नहीं, बल्कि क्रियान्वयन की मजबूत व्यवस्था भी मौजूद है। तेज अनुमतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योग-अनुकूल वातावरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

लखनऊ : महिला किराएदार से मकान मालिक ने किया दुष्कर्म,रिपोर्ट दर्ज

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई इलाके मे किराए पर रह रही विधवा महिला के साथ हैवानियत की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

पीडिता महिला ने अपने मकान मालिक के लकड़े पर नशीली काफी पीलाकर अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर 15 दिनो तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए डीसीपी से शिकायत किया। पीजीआई पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ मे जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार थाना पीजीआई क्षेत्र के ईश्वरीखेड़ा में किराये पर रह रही एक विधवा महिला का आरोप है कि करीब 28 दिन पहले मकान मालिक के लड़के ने नशीली कॉफी पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया इसके बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगभग 15 दिनों तक महिला को ब्लैकमेल करता रहा और जबरन दुष्कर्म करता रहा।

पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने गॉव पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद पिता ने ईश्वरीखेड़ा स्थित किराये का कमरा खाली करा दिया। इस बात की भनक लगते ही आरोपी ने महिला को फोन कर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी

शिवानंद को मिली है मिलेएरिया चौकी की कमान

मिलेएरिया चौकीः एक चुनौतीपूर्ण विरासत!

शिवानंद को मिली है मिलेएरिया चौकी की कमान, क्या वह कर पाएंगे अपराधों पर लगाम? , पूर्व के चौकी इंचार्ज अभिमन्यु के जाने के बाद मिलेएरिया चौकी की जिम्मेदारी शिवानंद को मिली है, क्या वह इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? मिलेएरिया चौकी की चुनौतियाँः - अपराधों की उच्च दर , - विवादों से घिरी चौकी - स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना, क्या शिवानंद इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और मिलेएरिया चौकी को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त क्षेत्र बनाएंगे?

प्रमुख समाचार

मेरठ, कपसाढ़ में बेटी का किडनैप, मां की हत्या मामला, सपा विधायक अतुल प्रधान को रोका गया, अतुल प्रधान को गांव जाने से रोका गया, पुलिस और अतुल में नोंकझोंक, धक्का-मुक्की, कपसाढ़-टांडा सड़क पर धरना दे रहे अतुल, समर्थकों के साथ पुलिस बैरीकेट के सामने धरना, मां का शव पुलिस ने परिजनों को सौंपा, पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया, डीएम, एसएसपी मौके पर मौजूद, सरधना के कपसाढ़ में बेटी किडनैप, मां की हत्या

लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरूआत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन

सीएम योगी ने फैक्ट्री पहुंचकर ई-बसों का अंदर से किया निरीक्षण

राजनाथ सिंह ने ई-बस में सफर कर परियोजना का लिया जायजा

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक , परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद

सरोजनी नगर में 70 एकड़ में बना अशोक लेलैंड का ईवी प्लांट

रिकॉर्ड 16 महीने में तैयार हुआ इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन

सरकार और कंपनी ने प्लांट को उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी औद्योगिक उपलब्धि बताया।